

## निर्मला बाला घोष और अन्य

बनाम

## बलाई चंद घोष और अन्य

29 मार्च, 1965

[के. सुब्बा राव, जे.सी. शाह और आर. एस. बाचावत, जे.जे.]

धार्मिक बंदोबस्ती-विनिमय-बंदोबस्त विलेख का निर्माण - बंदोबस्ती चाहे आंशिक हो या पूर्ण-निर्णय के लिए परीक्षण-शैबिट के रखरखाव के लिए प्रावधान क्या बंदोबस्ती को आंशिक बनाता है-विलेख के कुछ प्रावधानों की अमान्यता का प्रभाव-आय और स्थैतिक व्यय का विस्तार-अधिकार से अनुमान अपील करने के लिए संयुक्त शेषित का यदि देवताओं का प्रतिनिधित्व संरक्षक विज्ञापन वस्तु द्वारा किया जाता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5)-आदेश 41 नियम 33- प्रयोज्यता- जब डिक्री को गैर-अपील पक्ष के पक्ष में अपील में संशोधित किया जा सकता है।

**अभिनिर्धारित:** (i) प्रश्न कि क्या समर्पण का एक कार्य पूर्ण या आंशिक समर्पण बनाता है, कार्य के सभी प्रावधानों के एक पहलू से तय किया जाना चाहिए। यदि संपत्ति पूरी तरह से मूर्ति की पूजा के लिए समर्पित है और निपटानकर्ता, उसके वंशजों या अन्य व्यक्तियों के लिए कोई लाभकारी हित आरक्षित नहीं है, तो समर्पण पूरा हो गया है: यदि विलेख का उद्देश्य देवता के पक्ष में शुल्क कायम करना है और अवशेष बंदोबस्तकर्ता में निहित है, तो समर्पण आंशिक है।

(ii) शेबैट्स के पारिश्रमिक रखरखाव और निवास के लिए एक उचित प्रावधान एक बंदोबस्ती को बुरा नहीं बनाता है, भले ही संपत्ति पूरी तरह से एक मूर्ति को समर्पित हो, और बसने वाले के लिए कोई लाभकारी हित आरक्षित नहीं है, संपत्ति देवता के पास होती है एक आदर्श भाव संपत्ति का कब्जा और प्रबंधन, चीजों की प्रकृति में, शेबैट या 'प्रबंधक को सौंपा जाना चाहिए और संपत्ति में निवास के अधिकार के साथ संपन्न संपत्ति से उचित पारिश्रमिक के साथ निपटानकर्ता और उसके उत्तराधिकारियों का नामांकन अमान्य नहीं होगा। [556 ई-जी]

(iii) शेबैट के अलावा अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए एक प्रावधान वैध नहीं हो सकता है, यदि यह शाश्वतता या संचय के खिलाफ नियम का उल्लंघन करता है, या अस्वीकार्य प्रतिबंधों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करता है, लेकिन यह बंदोबस्ती की वैधता को प्रभावित नहीं करता है। अमान्य पाए गए प्रावधान में लाभकारी हित देवता या बंदोबस्तकर्ता को वापस कर दिया जाता है, क्योंकि बंदोबस्ती पूर्ण या आंशिक है। यदि पूर्ण बंदोबस्ती और अन्य व्यक्तियों के पक्ष में बनाया गया शुल्क अमान्य है, तो लाभ देवता को मिलेगा, और सेटलर या उसके उत्तराधिकारियों को वापस नहीं मिलेगा। [556 जी-एच]

(iv) ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब आय बढ़ रही है और व्यय स्थिर हैं, तो पर्याप्त अवशेष छोड़कर, यह माना जाना चाहिए, स्वभाव की व्यापक और अप्रतिबंधित प्रकृति के बावजूद निपटानकर्ता केवल पक्ष में एक शुल्क कायम करने का इरादा रखता है देवता का प्रश्न हमेशा निपटान विलेख के तहत सभी स्वभावों की समीक्षा से निर्धारित होने वाले निपटानकर्ता के इरादे का होता है। [560 जी]

सुरेंद्रकेशव रॉय बनाम दुर्गसुंदरी दाससी और अन्य। एलआर 19 आईए 108, समझाया गया।

श्री श्री ईश्वरी भुवनेश्वरी ठकुरानी बनाम ब्रोजोनाथ डेर और अन्य। एलआर 64 आईए 203 और श्री ईश्वर श्रीधर यहूदी बनाम सुशीला बाला देसी और अन्य। [1954] एससीआर 407, पर निर्भर।

सुब्बा राव और शाह, जे.जे. के अनुसार- जब देवताओं के संरक्षक ने विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष के खिलाफ अपील नहीं की कि आंशिक समर्पण हुआ था, तो यह एक संयुक्त शेष के लिए खुला नहीं था जो संरक्षक नहीं था, इसके खिलाफ अपील करने के लिए डिक्री और तर्क है कि समर्पण पूर्ण था।

जब कोई पक्ष डिक्री के विरुद्ध अपील न करके, प्रथम दृष्टया न्यायालय की डिक्री को अंतिम बनने की अनुमति देता है, तो यह मुकदमेबाजी के लिए किसी अन्य पक्ष के लिए खुला नहीं होगा, जिसके अधिकार अन्यथा डिक्री से प्रभावित नहीं होते हैं, आदेश 41 नियम 33 के तहत अपीलीय अदालत की शक्तियों का उपयोग करके अपील न करने वाले पक्ष के पक्ष में डिक्री पारित करना ताकि बाद वाले को वह लाभ दिया जा सके जिसका उसने दावा नहीं किया है। [564 डी]

बाचावत, जे. के अनुसार(आंशिक रूप से असहमत) - जब विचारण न्यायालय यह फैसला देता है कि देवताओं के पक्ष में बंदोबस्ती पूर्ण नहीं थी, और देवताओं के संरक्षक एडलिटिम अपील नहीं करते हैं, यह एक संयुक्त शेष के लिए भी खुला है जब वह अपील में डिक्री पर हमला करने वाला अभिभावक नहीं है। [565 ए]

महाराजा जगदीन्द्र नाथ रॉय बहादुर बनाम रानी हेमन्त कुमारी देबी, (1904) एलआर 31 आईए 203 पर भरोसा किया गया।

शेबैती अधिकार संपत्ति का अधिकार है। यह अधिकार इस घोषणा से प्रभावित होता है कि देवताओं के पक्ष में समर्पण आंशिक है, पूर्ण नहीं। पूर्ण नवोदित में शेबैती अधिकार आंशिक नवोदित में शेबैती अधिकार से भिन्न होता है। संयुक्त शेबैत अपने अधिकार की रक्षा करने का हकदार है, भले ही देवताओं के संरक्षक अपील न करें।  
[565 ई, एच]

हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी, [1954] एससीआर 1005, का उल्लेख किया गया है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1964 की सिविल अपील संख्या 966 958।

1957 की मूल डिक्री संख्या 268 से 270 तक की अपील में कलकत्ता उच्च न्यायालय के 23 सितंबर 1959 के फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील।

अपीलकर्ताओं के लिए एसवी गुप्ते, सॉलिसिटर-जनरल, एके सेन और डीएन मुखर्जी (सभी अपीलों में)।

प्रतिवादी नंबर 1 के लिए एवी विश्वनाथ शास्त्री और एससी मजूमदार।

सुब्बा राव और शाह जे जे का निर्णय। बचावत, जे. द्वारा आंशिक रूप से असहमति व्यक्त की गई थी।

शाह, जे. अपीलों का यह समूह आठवें अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में पहले प्रतिवादी बलाई चंद घोष (जिन्हें इसके बाद "बलाई" कहा जाएगा) द्वारा दायर किए गए 1954 के वाद संख्या 79 और 80 और 1955 के वाद संख्या 67 से उत्पन्न हुआ है। अलीपुर, जिला 24-परगना, पश्चिम बंगाल। 1955 के वाद संख्या 67 में उन्होंने

दावा किया कि यह घोषित किया जाए कि उनकी पत्नी निर्मला, उनके लिए एक बेनामीदार हैं और 15 सितंबर, 1944 को समर्पण का विलेख देवताओं के लिए संपत्तियों के पूर्ण समर्पण के बराबर नहीं था। श्री सत्यनारायण जिउ और श्री लक्ष्मीनारायण जिउ और वादी दोनों देवताओं का एकमात्र शेष है। अधिनस्थ न्यायालय ने 1954 के वाद संख्या 79 और 80 पर फैसला सुनाया कि वादी विवादित संपत्तियों का मालिक था और 8 मार्च 1939 को निर्मला द्वारा निष्पादित बंदोबस्ती का विलेख ईएक्स्टी 11 (ए) "दिखावटी और बनावटी" था। 1955 के वाद संख्या 67 में अधीनस्थ न्यायाधीश ने घोषणा की कि निर्मला मुकदमे में संपत्तियों और 15 सितंबर, 1944, विस्तार के बंदोबस्ती के विलेख ईएक्स्टी. 11 के बलाई की बेनामीदार थी। देवताओं श्री सत्यनारायण जेउ और श्री लक्ष्मीनारायण जेउ को संपत्तियों का पूर्ण समर्पण नहीं था।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को संशोधित किया। उच्च न्यायालय ने माना कि विलेख ईएक्स्टी. 11(ए) दिखावा नहीं था, बल्कि यह देवता श्री गोपाल जेउ के पक्ष में आंशिक समर्पण था यानी इसने विलेख में उल्लिखित देवता के प्रयोजनों के लिए दी गई संपत्तियों पर एक आरोप लगाया। 1955 के वाद संख्या 67 में पारित डिक्री, जिसमें से 1957 की अपील नंबर 269 उत्पन्न हुई थी, को "स्पष्टीकरण या स्पष्टीकरण" के अधीन खारिज कर दिया गया था कि इसने उसमें बताए गए उद्देश्यों और उस विषय के लिए शहर या देवताओं के पक्ष में केवल एक आरोप बनाया था। आरोप के अनुसार, संपत्तियां बलाई की थीं। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ, इन तीन अपीलों को प्राथमिकता दी गई है।

[उन तथ्यों को बताने के बाद जिन्होंने अपीलों को जन्म दिया, महामहिम आगे बढ़े]

हम विलेख ईएक्स्टी. 11(ए) की शर्तों को संक्षेप में निर्धारित कर सकते हैं। इसे देवता के सेवा के लिए 20,000 रुपये की कीमत वाली अचल संपत्तियों के संबंध में समर्पण के विलेख के रूप में वर्णित किया गया है। संपत्तियों का वर्णन करने के बाद यह पढ़ा जाता है कि सेटलर के पास संपत्तियों का कब्जा और उपभोग था और उसने संपत्तियों को देव-सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। फिर विलेख में कहा गया है कि बंदोबस्तकर्ता अपने पति द्वारा स्थापित श्री गोपाल जेठ के सेवा को चला रही थी, और उसके पति द्वारा समर्पित संपत्तियां श्री गोपाल जेठ के सेवा को हमेशा के लिए संतोषजनक ढंग से चलाने और नामों को कायम रखने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। उसके ससुर और सास की ओर से और श्री गोपाल जेठ के देवता की पूजा के कार्य को नियमित रूप से हमेशा के लिए जारी रखने के लिए, तब निर्धारित प्रावधान किए गए थे। विलेख यह बताने के लिए आगे बढ़ता है:

"मैं उपरोक्त दो संपत्तियों को नीचे दी गई अनुसूची में पूरी तरह से वर्णित करके समर्पित करती हूँ ताकि मेरे पति द्वारा स्थापित श्री श्री गोपाल ठाकुर की दैनिक और आवधिक सेवा आदि नियमित रूप से चलती रहे। इस दिन से उक्त दोनों संपत्तियां बन गईं उक्त 'देवता श्री श्री गोपाल जेठ ठाकुर की डेब्यूटर संपत्तियां और वे इसमें निहित हैं, जो बाधाओं और दोषों से बिल्कुल मुक्त हैं। उक्त देवता श्री श्री गोपाल जेठ उक्त दो संपत्तियों के पूर्ण-स्वामी बन जाते हैं। इस संबंध में न तो मैं और न ही मेरा कोई उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि कोई मुद्दा उठाएगा या किसी भी समय कोई दावा या मांग करने का हकदार होगा और यदि ऐसा किया भी जाता है तो यह पूरी तरह से शून्य और खारिज कर दिया जाएगा।"

तब विलेख में निर्देश दिया गया है कि "श्री गोपाल जीठ ठाकुर के लिए लगभग 500/- रुपये मूल्य का एक अच्छा मंदिर और आभूषण श्री गोपाल जीठ ठाकुर की

डेब्यूटर संपत्तियों की आय से बनाया जाएगा और मंदिर का निर्माण किया जाएगा, देवता को वहां स्थापित किया जाएगा और पूजा आदि और ब्राह्मणों के मनोरंजन और समारोह के संबंध में अन्य खर्चों को श्री गोपाल जिठ ठाकुर की डेब्यूटर संपत्तियों की आय से पूरा किया जाएगा।"

देवता की पूजा के खर्चों को पूरा करने के लिए, अनुसूची में वर्णित संपत्तियों को निर्देशित किया गया था, उन्हें किराए पर दिया जाएगा और देवता के सभी खर्चों को किराए से निकाल दिया जाएगा, जिसका शेष उचित हिसाब-किताब रखेगा। आय और व्यय को देवता के कोष में जमा करें और जो भी अधिशेष हो उसे देवता के कोष में जमा करें, वार्षिक रूप से घरों की मरम्मत करें, नगरपालिका कर आदि का भुगतान करें, और अधिशेष आय से प्राप्त राशि से देवता के नाम पर अचल संपत्ति खरीदें और उस आय से देवता के यहां एक घर बनाएं। 153, बेलियाघाटा मेन रोड और उस घर का किराया डेब्यूटर फंड में जमा करें। विलेख शेबेटशिप के उत्तराधिकार के संबंध में विस्तृत निर्देश देता है। विलेख द्वारा निर्मला और उसके पति बलाई को संयुक्त शेष बनाया गया और यह निर्देश दिया गया कि निर्मला की मृत्यु के बाद बलाई शेष होंगे, और उनकी मृत्यु के बाद उनके दो बेटे परेश और नरेश देवता के शेष बन जाएंगे। सेटलर ने आशा व्यक्त की कि दो शेष और उनके वंशज परिवार के सदस्यों के रूप में एक ही रिवाज में रहेंगे और निर्देश दिया कि जो कोई भी रिवाज में अलग हो गया वह देवता का शेष होने का हकदार नहीं होगा, लेकिन अगर वे रिवाज में अलग हो गए आवास की कमी के लिए "अपनी मर्जी से और एकमत होने के नाते", और सभी संपत्तियां संयुक्त रहती हैं, वे शेष बने रहने के हकदार होंगे। दो पुत्रों, परेश और नरेश की मृत्यु पर, उनके पुत्र शेबेटशिप में अपने-अपने पिता के हिस्से के अनुसार शेष बन जाएंगे, और यदि किसी भी बेटे के एक से अधिक बेटे हैं, तो ऐसे सभी बेटों को एक साथ पिता

के स्थान पर पूजा की बारी मिल जाएगी और विलेख की शर्तों के अनुसार कार्य करेगा और देवता की पूजा जारी रखेगा और बेटों की अनुपस्थिति में, सेटलर के महान पोते को शेष नियुक्त किया जाएगा, और वे डेबटर संपत्ति की रक्षा करेंगे। इसके बाद विलेख यह निर्देश देता है कि दैनिक सेवा को बलाई द्वारा बनाए गए डेब्यूटर से संबंधित समर्पण के विलेख में निर्धारित तरीके से ही चलाया जाएगा और देवता की पूजा के लिए दैनिक और आवधिक खर्च बलाई द्वारा समर्पित डेब्यूटर संपत्तियों से पूरा किया जाएगा। तब प्रावधान किया गया था कि जन्माष्टमी, रासजात्रा और श्री गोपाल जिउ ठाकुर के प्रत्येक त्योहार के अवसर पर शेष द्वारा ब्राह्मणों और गरीबों के मनोरंजन के लिए 101/- रुपये की राशि खर्च की जाएगी। सेवार्ट के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को 25/- रुपये का मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है और यह निर्देश दिया गया है कि जब तक बेटे संयुक्त सामूहिकता में शेष बने रहेंगे, उन्हें अपने सामान्य पारिवारिक खर्च के लिए प्रति माह चार मन चावल, दो मन आटा और "दैनिक खर्च के लिए" 2/- रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। संक्रान्ति के दिन अर्थात् प्रत्येक माह के अंतिम दिन 10/- रुपये प्रति माह की अतिरिक्त राशि और शिवरात्रि के अवसर पर 51/- रुपये की राशि डेब्यूटर एस्टेट से बाहर खर्च करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश दिया गया है कि इन सभी खर्चों को घर के किराए और डेब्यूटर संपत्तियों की बस्ती की भूमि के मासिक टिक्का किराए से पूरा किया जाना है, लेकिन शेष स्थायी अधिकारों में घर या जमीन को किराए पर देने के हकदार नहीं हैं। किसी को भी बंधक रखने, उपहार देने, बेचने, भार उठाने या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है, और यदि घर में कोई किरायेदार नहीं है या बस्ती का किराया वसूल नहीं किया गया है, तो देवताओं का खर्च कम कर दिया जाएगा और शेष को आनुपातिक रूप से पारिश्रमिक कम कर दिया जाएगा। शेष के कार्यालय के हस्तांतरण के लिए प्रावधान किया गया



है। जब तक संपूर्ण पुरुष वंश विलुप्त नहीं हो जाता, तब तक महिला वंश के वंशजों को शेबेटशिप से बाहर रखा जाता है। डेब्यूटर संपत्ति के लिए प्राप्त मुआवजे के आवेदन के लिए भी प्रावधान किया गया है: यह निर्देश दिया गया है कि मुआवजे की राशि में से शेबेट्स द्वारा देवता के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदी जाएंगी या राशि को सरकारी कागज में नाम पर निवेश किया जाएगा। देवता का, और उसके ब्याज से विलेख में निर्देशित संवितरण किया जाएगा। फिर विलेख यह निर्देश देता है कि पूजा की लागत को पूरा करने के बाद शेष अतिरिक्त राशि जमा की जाएगी। शेबैट्स को डेब्यूटर एस्टेट से जुड़े घरों में रहने या अन्यथा उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है और यह निर्देश दिया गया है कि यदि कोई इसमें निवास करता है या इसका उपयोग करता है, तो वह उचित किराया देने के लिए बाध्य रहेगा। विलेख का अनुच्छेद 12 फिर प्रदान करता है:

""अगर भविष्य में शेबैटों को अपने निवास के लिए कमरों की कमी होगी तो उनमें से प्रत्येक को बस्टी नंबर 153 के भीतर तीन कोट्टा जमीन लेनी होगी, बेलियाघाटा मुख्य सड़क दक्षिणी छोर से शुरू होती है और अपने खर्च पर उस पर मकान बनाने के बाद वह अपने बेटों को इसका आनंद लेना और अपने पास रखना जारी रखेगा, बेलियाघाटा मुख्य सड़क दक्षिणी छोर से शुरू होती है और अपने खर्च पर उस पर मकान बनाने के बाद वह अपने बेटों को इसका आनंद लेना और अपने पास रखना जारी रखेगा।"

यदि कोई शेबैट घर बनाने के बाद पुत्रहीन मर जाता है, तो उसकी विधवा अपने जीवनकाल के दौरान घर में रहने की हकदार होगी और भोजन और 5 रुपये प्रति माह खर्च पाने की भी हकदार होगी। विलेख फिर कहता है:

"यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय उक्त बस्ती में बने घर के संबंध में उपहार, बिक्री या हस्तांतरण करने का हकदार नहीं होगा। उक्त घर डेब्यूटर एस्टेट का एक हिस्सा बनेगा और केवल शेषित समान कब्जे में रहेगा"।

अंत में, विलेख में कहा गया है कि विलेख में बताए गए प्रभाव के अनुसार निपटानकर्ता अपने पति द्वारा स्थापित श्री ईश्वर गोपाल जेठ ठाकुर को "नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति आदि" देती है।

प्रस्तावना के साथ-साथ विलेख के ऑपरेटिव भाग में, यह कहा गया है कि निपटानकर्ता ने अनुसूची में वर्णित संपत्तियों को श्री गोपाल जेठ ठाकुर की पूजा करने के उद्देश्य से समर्पित किया है। विलेख स्पष्ट रूप से बताता है कि समर्पण के विलेख द्वारा संपत्तियां देवता की संपत्ति बन गई हैं और वे सभी बाधाओं से मुक्त होकर देवता में निहित हैं, और किसी अन्य व्यक्ति का उस पर कोई अधिकार नहीं है। विलेख में निस्संदेह कुछ असंगत निर्देश शामिल हैं, लेकिन समर्पण का प्रमुख विषय यह है कि संपत्ति देवता श्री गोपाल जेठ की है और किसी और का इसमें कोई लाभकारी हित नहीं है।

दो मुकदमों में बलाई द्वारा उठाई गई दलील यह थी कि समर्पण का विलेख ईएक्स्टी. 11(ए) "केवल बनावटी था और उस पर कभी कार्रवाई नहीं की गई" और इस कार्य से उसके शीर्षक पर "एक बादल छा गया"। निचली अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली। उच्च न्यायालय ने माना कि विलेख वैध था, लेकिन इसके द्वारा केवल आंशिक समर्पण का इरादा था। देवता श्री गोपाल जीठ के पक्ष में एक वास्तविक बंदोबस्ती है, यह अब विवाद में नहीं है। प्रचारित एकमात्र प्रश्न यह है कि समर्पण आंशिक है या पूर्ण।

बलाई का तर्क है कि यह आंशिक है: निर्मला द्वारा प्रस्तुत देवता का तर्क है कि यह पूर्ण है। जहां समर्पण का एक विलेख है, यह प्रश्न कि क्या यह पूर्ण या आंशिक समर्पण बनाता है, विलेख के सभी प्रावधानों के एक पहलू से तय किया जाना चाहिए। यदि संपत्ति पूरी तरह से मूर्ति की पूजा के लिए समर्पित है और बसने वाले, उसके वंशजों या अन्य व्यक्तियों के लिए कोई लाभकारी हित आरक्षित नहीं है, तो समर्पण पूरा हो गया है: यदि विलेख द्वारा जो बनाने का इरादा है वह देवता के पक्ष में एक आरोप है और अवशेष बंदोबस्तकर्ता के पास निहित है, समर्पण आंशिक है। बलाई के वकील का तर्क है कि समर्पण विलेख में बार-बार इस दावे के बावजूद कि संपत्ति श्री गोपाल जिउ के पक्ष में दी गई थी और यह मूर्ति के स्वामित्व में थी, विलेख में विभिन्न दिशा-निर्देश शामिल थे जो संकेत देते थे कि समर्पण का उद्देश्य आंशिक था। वकील ने तर्क के समर्थन में विलेख में निम्नलिखित संकेतों पर भरोसा किया:

(1) पुरुष वंश में बसने वाले के वंशजों को शेबेट्स के रूप में कार्य करने का वंशानुगत अधिकार दिया गया था, और उनके निवास, रखरखाव और खर्चों के लिए प्रावधान किया गया था। यह केवल शेबैट्स तक ही सीमित नहीं था, बल्कि शेबैट्स के परिवारों के सदस्यों के लाभ के लिए सुनिश्चित किया गया था।

(2) संपन्न संपत्ति की आय देवता के खर्चों के लिए आवश्यक रकम से अधिक थी। यह तर्क दिया गया कि देवता के खर्च स्थिर थे, जबकि आय का विस्तार हो रहा था, जिससे एक बड़ा अधिशेष अप्रयुक्त रह गया था। संपत्ति की ठेकेदारी से आय होने पर देवता के खर्चों को कम करने का प्रावधान किया गया।

(3) यह विलेख देवता के लाभ के लिए बलाई द्वारा निष्पादित एक अन्य विलेख का पूरक था, और देवता का खर्च मुख्य रूप से उस विलेख के तहत दी गई संपत्ति से आना था।

(4) संचय के निपटान के लिए किसी भी प्रावधान के बिना, प्राप्त संपत्ति और अर्जित की जा सकने वाली अन्य संपत्तियों की आय के संचय के लिए निर्देश, सेटलर की ओर से लाभ के लिए संपत्ति को हमेशा के लिए बांधने के इरादे का खुलासा करता है। पुरुष वंशज देवता के पक्ष में एक निश्चित शुल्क के अधीन होते हैं।

हम उन निर्देशों की वैधता या अन्यथा पर कोई राय व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, जिसके तहत आय संचय का प्रावधान किया जाता है या संबंधित शेबेट्स के अलावा अन्य व्यक्तियों को लाभ दिया जाता है। यह जांच केवल इस सवाल की ओर निर्देशित है कि क्या इस धारणा पर कि दिशा-निर्देश वैध हैं, वे निपटानकर्ता की ओर से बसने वाली संपत्ति पर केवल एक शुल्क बनाने के इरादे का संकेत देते हैं, जो कि निपटानकर्ता या उसके उत्तराधिकारियों में लाभकारी हित को सुरक्षित रखता है।

शेबेट्स के पारिश्रमिक, रखरखाव और निवास के लिए एक उचित प्रावधान एक बंदोबस्ती को बुरा नहीं बनाता है, भले ही संपत्ति पूरी तरह से एक मूर्ति को समर्पित हो, और बंदोबस्तकर्ता के लिए कोई लाभकारी हित आरक्षित नहीं है, संपत्ति एक आदर्श अर्थ में देवता के पास होती है। संपत्ति का कब्जा और प्रबंधन, चीजों की प्रकृति में, एक शेबैत या प्रबंधक को सौंपा जाना चाहिए और संपत्ति में निवास के अधिकार के साथ संपन्न संपत्ति से उचित पारिश्रमिक के साथ निपटानकर्ता और उसके उत्तराधिकारियों का नामांकन अमान्य नहीं होगा। बंदोबस्ती. शेबैत के अलावा अन्य व्यक्तियों के लाभ के

लिए एक प्रावधान वैध नहीं हो सकता है, अगर यह शाश्वतता या संचय के खिलाफ नियम का उल्लंघन करता है, या अभेद्य प्रतिबंधों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करता है, लेकिन यह बंदोबस्ती की वैधता को प्रभावित नहीं करता है। अमान्य पाए गए प्रावधान में लाभकारी हित देवता या बंदोबस्तकर्ता को वापस कर दिया जाता है, क्योंकि बंदोबस्ती पूर्ण या आंशिक है। यदि बंदोबस्ती पूर्ण है, और अन्य व्यक्तियों के पक्ष में बनाया गया शुल्क अमान्य है, तो लाभ देवता को मिलेगा, और सेटलर या उसके उत्तराधिकारियों को वापस नहीं मिलेगा।

श्री गोपाल जेठ के पक्ष में बंदोबस्ती की आय के बारे में साक्ष्य कुछ अस्पष्ट और अनिश्चित हैं। बलाई द्वारा उस देवता के लिए निष्पादित बंदोबस्ती का विलेख ईएक्सटी. 11(ए) अनुपूरक न्यायालय के समक्ष नहीं है, और उस बंदोबस्ती से आय और उसके तहत दिए गए निर्देशों के बारे में रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। रिकॉर्ड में दोष सीधे तौर पर प्रथम दृष्टया न्यायालय में बलाई द्वारा उठाई गई याचिका की प्रकृति से पता लगाया जा सकता है। उन्होंने दलील दी थी कि उनकी पत्नी निर्मला द्वारा की गई बंदोबस्ती एक्सटेंशन 11 (ए) एक "दिखावा लेनदेन" था और इसका उद्देश्य देवता में कोई रुचि पैदा करना नहीं था। यह बलाई का मामला नहीं था कि बंदोबस्ती वैध होते हुए भी आंशिक थी और देवता के पक्ष में संपत्ति पर केवल एक आरोप लगाया गया था। 1954 के वाद संख्या 79 और 80 पर 1955 के वाद संख्या 67 के साथ मुकदमा चलाया गया और सवाल यह था कि क्या श्री गोपाल लियू के पक्ष में बंदोबस्ती आंशिक थी या ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मुकदमों में बिना किसी दलील के इसे पूर्ण रूप से उठाया गया है। हालाँकि, मामले के इस हिस्से पर कुछ सबूत हैं, जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है, और जिस पर बलाई के वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित

डिक्री का समर्थन करने के लिए तर्क दिया है। समर्पण के विलेख ईएक्स्टी. 11(ए) "एक अच्छा मंदिर और लगभग 500 रुपये मूल्य के आभूषण" प्रदान की गई संपत्ति में से प्रदान किए जाने हैं। जन्माष्टमी, रासजात्रा और अन्य त्यौहार प्रतिवर्ष मनाए जाने हैं और इनमें से प्रत्येक त्यौहार के संबंध में रु. 101/- खर्च करने होंगे. शेबैत का पारिश्रमिक 25/- प्रति माह रुपये निर्धारित है और शेबैत के परिवार के लाभ के लिए चार मन चावल, दो मन आटा और दैनिक खर्च के लिए 2/-रुपये प्रतिदिन की राशि प्रदान किये जाते हैं। हर महीने संक्रांति के दिन श्री सत्यनारायण जेठ की सेवा करने के लिए रु. 10/- खर्च करने होंगे और 51/- रुपये शिवरात्रि के दिन खर्च करने होंगे, भुगतान का प्रावधान किया गया है। परिवार की धर्मपरायण विधवा को पूजा में मदद के लिए 2/- रुपये प्रति माह और शेबैत की विधवा को 5/- रुपये प्रति माह की दर से खर्च का भुगतान करना होगा, कुल मिलाकर, इनकी राशि 1939 में प्रचलित दरों पर 2,400/- रुपये प्रति वर्ष होगी।

बस्ती भूमि 153/1 से बंदोबस्ती की तिथि पर आय निर्मला द्वारा 50/- रुपये प्रति माह होने का अनुमान लगाया गया था, और मकान नंबर 155 और 154/2 से आय 200/- रुपये आंकी गई। यहां नगरपालिका या अन्य करों, किराया संग्रहण व्यय और मरम्मत के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। किन रिकॉर्ड पर मिली सामग्रियों के आधार पर, यह दलील कि संपत्तियों की आय काफी हद तक किए जाने वाले कुल खर्च से अधिक थी, स्वीकार नहीं की जा सकती। बंदोबस्तकर्ता ने प्रावधान किया था कि यदि कोई शेबैत घर में रहने में असमर्थ है, तो वह 2/- रुपये प्रति माह की दर से परिसर संख्या 153 से बाहर जमीन का एक टुकड़ा पाने का हकदार होगा: चाहे यह किराया नाममात्र का हो या वास्तविक, जांच की जरूरत नहीं है। यदि शेबैत के निवास का प्रावधान उसकी वैधता को प्रभावित किए बिना बंदोबस्ती के विलेख के तहत किया जा

सकता है, एक प्रावधान जिसके तहत शेबैट विशेष रूप से कम दरों पर देवता से संबंधित भूमि का उपयोग करने का हकदार होगा, वह अपने आप में बंदोबस्तकर्ता द्वारा एक अनुचित आरक्षण के बराबर नहीं हो सकता है। यह दलील कि यह एक अनुकरणीय बंदोबस्ती थी, बलाई द्वारा छोड़ दी गई है। इसलिए यह मानते हुए कि मासिक किराये के रूप में शेबैट्स से लिया जाने वाला किराया नाममात्र था, उस आधार पर समर्पण विलेख की वैधता प्रभावित नहीं होगी। शेबैट्स द्वारा भविष्य में घर बनाने के लिए भूमि का उपयोग निस्संदेह बाजार दरों पर किराए पर देने के लिए उपलब्ध भूमि को कम कर देगा। यदि देवता की वार्षिक आय 3,000/- रुपये प्रति वर्ष थी, और बलाई द्वारा निष्पादित बंदोबस्ती के विलेख के तहत कुछ आय, किराए के लिए संग्रह शुल्क, मरम्मत के खर्चों और निवर्तमान करों के अलावा 2,400/- रुपये थी, यह मानना उचित होगा कि 1939 में देवता को प्राप्त कुल आय और अनुमानित आय के बीच बहुत अधिक असमानता नहीं थी। तथ्य यह है कि कलकत्ता शहर में भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण, अचल संपत्ति का किराया बाद में बढ़ गया होगा, यह तय करने में अप्रासंगिक होगा कि क्या विलेख द्वारा पर्याप्त अवशेष का निपटान नहीं किया गया था। विलेख के पैराग्राफ 6 में यह निर्देश कि किराया वसूल न होने की स्थिति में, देवता के खर्चों को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा और शेबैट्स को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक में भी आनुपातिक कमी की जाएगी, भी महत्व प्राप्त करता है।

क्या बंदोबस्ती की आय के संचय का प्रावधान वैध है, इस मामले में निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। यदि पूर्ण समर्पण है, लेकिन संचय की दिशा अमान्य है, तो आय का लाभ बिना किसी प्रतिबंध के देवता के लाभ के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। आय निपटानकर्ता को वापस नहीं की जाएगी।

उच्च न्यायालय ने पाया कि यह कार्य देवता के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ शुरू हुआ था, लेकिन यह स्पष्ट था कि विलेख के तहत देवताओं की सेवा-पूजा और अन्य खर्चों का विस्तार करने योग्य चरित्र नहीं था, विलेख में विशिष्ट पाठ हैं जो संकेत देते हैं कि समर्पण केवल देवता की सेवा-पूजा आदि के लिए बलाई द्वारा बंदोबस्ती के पहले विलेख का पूरक था। उच्च न्यायालय ने कहा:

"वास्तव में, विलेख में ही विशिष्ट पाठ था, जिससे संकेत मिलता था कि यह केवल पति बलाई चंद्र घोष के पहले डेब्यूटर विलेख का पूरक था, जिसका उद्देश्य उक्त सेवा पूजा आदि को नियमित और संतोषजनक तरीके से चलाने में सक्षम करना था। व्यावहारिक रूप से सभी खर्चों का उल्लेख विलेख में ही किया गया है और संपत्ति की प्रकृति और आय के अनुमान को ध्यान में रखते हुए वे कितने भी विस्तृत क्यों न हों, जैसा कि हमारे सामने साक्ष्य में दिखाई दे रहा है, यह कहना मुश्किल है कि उक्त आय का कोई बड़ा हिस्सा उन खर्चों पर खर्च किया जाएगा। यह, निस्संदेह, यह मानने के पक्ष में एक मजबूत परीक्षण है कि विलेख की अनुसूची में उल्लिखित संपत्तियों में से उन खर्चों के लिए शुल्क का सृजन क्या था। इसके अलावा इस विलेख के तहत (ईक्स्टी.॥ (ए)) (खंड 3 के तहत) जहां तक दैनिक और आवधिक सेवा के खर्चों का संबंध है, या कम से कम, दैनिक सेवा खर्च, निश्चित और सामयिक दोनों, थे पति (बलाई चंद्र) के पहले डेब्यूटर से पूरा किया जाएगा, जिससे व्यावहारिक रूप से इस विलेख ईक्स्टी.११(ए) द्वारा कवर की गई संपत्तियों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। यह सच है कि इस विलेख (ईक्स्टी.११(ए)) के कई स्थानों में, डेब्यूटर एस्टेट की आय या डेब्यूटर एस्टेट के लाभों या डेब्यूटर एस्टेट में निवेश का संदर्भ दिया गया है, लेकिन वे सभी, संदर्भ में, को डेब्यूटर एस्टेट के संदर्भ में पढ़ा जा सकता है, जिसे प्रश्न में समर्पण द्वारा बनाया गया था, अर्थात्, आंशिक डेब्यूटर या चार्ज जो विशेष देवता के पक्ष में



बनाया गया था। जहां एक चार्ज बनाया जाता है और एक समर्पण किया जाता है, यह समर्पित संपत्तियों को डेब्यूटर के रूप में संदर्भित करना अनुचित नहीं होगा, हालांकि केवल उस शुल्क को प्रदान करने के सीमित उद्देश्य के लिए। यह, वास्तव में, आंशिक समर्पण का अर्थ है, जैसा कि हिंदू कानून में समझा जाता है। 'डेब्यूटर' शब्द का मात्र उपयोग 'जरूरी नहीं कि एक विशेष बंदोबस्ती को एक पूर्ण डेब्यूटर का गठन किया जाए। उसी सिद्धांत पर और उसी संदर्भ में, शेबैट्स द्वारा किराए का भुगतान, उनके निवास के प्रयोजनों के लिए समर्पित संपत्तियों के विशेष हिस्से पर कब्जा करते हुए, भी समझाया जा सकता है। तथ्य की बात के रूप में, संपूर्ण विलेख को पढ़ने पर, इस मामले की परिस्थितियों के प्रकाश में और उस पर पूर्ण विचार करने पर, हम इस विलेख, ईक्स्टी.11(ए) को मानने के इच्छुक हैं। इसके वास्तविक निर्माण पर, एक पूर्ण डेब्यूटर नहीं बनाया, बल्कि विभिन्न सेवाओं और अन्य आवश्यकताओं के लिए, उसमें नामित देवता श्री श्री गोपाल जेठ के पक्ष में केवल एक शुल्क बनाया, जो कि उक्त विलेख ईक्स्टी.11(ए) के कई पैराग्राफों में संदर्भित है।"

उच्च न्यायालय ने कहा कि क्योंकि संपन्न संपत्तियों की आय बड़ी थी और निरंतर विस्तार करने में सक्षम थी, और देवता के उद्देश्यों के लिए खर्च तय थे, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सेटलर का इरादा केवल एक शुल्क बनाने का था, न कि पूर्ण देवता के पक्ष में समर्पण। इस प्रस्ताव के समर्थन में, उच्च न्यायालय ने सुरेंद्रकेशव राँय बनाम दूरगसुंदन दाससी और अन्य(1) में न्यायिक समिति के फैसले पर मजबूत भरोसा जताया। उस मामले में राजा बिजायकेशव राँय ने शीबा और अन्य समारोहों के उचित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी वसीयत की संपत्ति एक ठाकुर को दे दी और अपनी दो विधवाओं को एक-एक बेटा गोद लेने का निर्देश दिया, ऐसे दोनों बेटों को शेबैत नियुक्त किया गया, जो कि नियंत्रण के अधीन थे। अवयस्कता

के दौरान विधवाओं को अतिरिक्त आय से मासिक भत्ता मिलता है। अवशेष का निस्तारण नहीं किया गया। न्यायिक समिति के समक्ष यह आग्रह किया गया था कि सारी संपत्ति राजा की इच्छा के तहत देवता को सौंप दी गई थी और बसने वाले के उत्तराधिकारी शेष बच गए थे और केवल सामान्य तरीके से संपत्ति का प्रबंधन करने के हकदार थे। उस विवाद से निपटने में न्यायिक समिति ने पी. पर अवलोकन किया।

127:

"यह सच है कि वसीयत के पहले वाक्य से सब कुछ ठाकुर को दे दिया जाता है; और हालांकि मुकदमे में यह सवाल उठाया गया है कि क्या उपहार वास्तविक बनाया गया है (और निश्चित रूप से ऐसे उपहार परिवार को बनाने की एक योजना मात्र हो सकते हैं) अविभाज्य संपत्ति), इस पर वास्तव में विवाद नहीं किया गया है। न ही वास्तव में इस मामले में इसे विवादित किया जा सकता है। वसीयत के अंतिम भाग में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि आय को सबसे पहले ठाकुर की सेवा करने में लगाया जाना था, जिसका उल्लेख उपहार की वस्तु के रूप में किया गया है, और अन्य परिवार ठाकुरों के, और निर्धारित मासिक भत्ते को पूरा करने में, और दैनिक और निश्चित संस्कारों और समारोहों को करने में 'जैसा कि अब किया और मनाया जाता है'। वसीयतकर्ता को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि बाद में इन सभी शुल्कों को पूरा कर दिया गया था तो एक बहुत बड़ा अधिशेष होगा। वास्तव में उनका निर्देश है कि अधिशेष में से प्रत्येक दत्तक पुत्र को 1,000/- रुपये मासिक मिलेंगे; लेकिन उसके बाद के शेष के बारे में वह कुछ नहीं कहते हैं।

इस बात का कोई संकेत नहीं है कि वसीयतकर्ता का इरादा ठाकुर परिवार की पूजा को आगे बढ़ाने का था। वह, जैसा कि कभी-कभी किया जाता है, दूसरों को पूजा के लाभ के लिए स्वीकार नहीं करता है। वह किसी अतिरिक्त समारोह का निर्देशन नहीं

करता है। वह उस चीज को छोड़कर कोई इरादा नहीं दिखाता है जिसका श्रेय उचित रूप से एक धर्मनिष्ठ हिंदू सज्जन को दिया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह पारिवारिक पूजा सामान्य तरीके से आयोजित की जाएगी। अपनी संपत्ति उन ठाकुरों में से एक को देकर, जिनका वह सबसे अधिक आदर करता है। लेकिन इसका प्रभाव, जब संपत्ति बड़ी होती है, तो कुछ लाभकारी हितों को बिना निपटान के छोड़ देना होता है, और वह ब्याज संपत्ति की कानूनी घटनाओं के अधीन होना चाहिए।"

लेकिन निर्णय में कोई नियम नहीं दिया गया है कि जहां आय बढ़ रही है और व्यय स्थिर हैं, एक बड़ा अवशेष छोड़कर, यह माना जाना चाहिए, स्वभाव की व्यापक और अप्रतिबंधित प्रकृति के बावजूद, कि निपटानकर्ता केवल एक शुल्क बनाने का इरादा रखता है देवता के पक्ष में. प्रश्न हमेशा निपटान विलेख के तहत सभी स्वभावों की समीक्षा से निर्धारित होने वाले निपटानकर्ता के इरादे का होता है।

श्री श्री ईश्वरी भुवनेश्वरी ठकुरानी बनाम ब्रोजोनाथ डे और अन्य(1) मामले में कुछ संपत्तियाँ दो भाइयों द्वारा एक घरेलू देवता को समर्पित की गईं और यह निर्देशित किया गया कि शैबैत का अधिकार ज्येष्ठाधिकार द्वारा उनके पुरुष उत्तराधिकारियों को जाना चाहिए। किसी विवाद से निपटने में, क्या समझौते के विलेख के तहत, देवता के प्रति पूर्ण समर्पण था, न्यायिक समिति ने पृष्ठ 211 पर देखा:

"समर्पण इस तथ्य के कारण अमान्य नहीं है कि सेटलर के परिवार के सदस्यों को शैबैट्स के रूप में नामित किया गया है और बंदोबस्ती से उचित पारिश्रमिक दिया गया है और समर्पित संपत्ति में निवास के अधिकार भी दिए गए हैं। समर्पित संपत्ति से जुड़े विशेषाधिकारों को ध्यान में रखते हुए ऐसा अक्सर नहीं हुआ है, जैसा कि कानून

रिपोर्ट से पता चलता है, अनुकरणीय समर्पण किए गए हैं, और समर्पण के किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य की बारीकी से जांच यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि क्या मूर्ति के पक्ष में सेटलर द्वारा वास्तविक विनिवेश किया गया है। इसके अलावा, समर्पण या तो पूर्ण या आंशिक हो सकता है। संपत्ति मूर्ति को दी जा सकती है, या मूर्ति के पक्ष में शुल्क के अधीन हो सकती है। 'सवाल यह है कि क्या मूर्ति को ही सच्चा लाभार्थी माना जाएगा, जो उनके रखरखाव के लिए वसीयतकर्ता के उत्तराधिकारियों या निर्दिष्ट रिश्तेदारों के पक्ष में शुल्क के अधीन होगा, या दूसरी ओर, इन उत्तराधिकारियों को संपत्ति का सच्चा लाभार्थी माना जाएगा, विषय मूर्ति के रखरखाव, पूजा और खर्च के लिए शुल्क एक ऐसा प्रश्न है जिसे वसीयत के संपूर्ण प्रावधानों के एक पहलू से ही तय किया जा सकता है', पांडे हर नारायण बनाम सुरजू कंवारी (एलआर 43 1.ए.) 143). मूर्ति की पूजा में होने वाले खर्च और मनाए जाने वाले समारोहों के संबंध में समर्पित की जाने वाली कथित संपत्ति की सीमा पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। समर्पण के उद्देश्यों को आय बढ़ने के साथ विस्तारित करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है, या उद्देश्यों को सीमित शर्तों में निर्धारित किया जा सकता है ताकि यदि आय इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक सीमा से अधिक बढ़ जाए तो इसे समर्पण द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है।

इस न्यायालय के एक हालिया फैसले श्री ईश्वर श्रीधर जिउ बनाम सुशीला बाला दासी और अन्य (1) में यह देखा गया कि यह सवाल कि क्या मूर्ति ही वास्तविक लाभार्थी है, वसीयतकर्ता के उत्तराधिकारियों के पक्ष में आरोप के अधीन है, या उत्तराधिकारी सच्चे लाभार्थी हैं, जो मूर्ति के रखरखाव, पूजा और खर्च के लिए शुल्क के अधीन हैं, संपूर्ण विलेख या वसीयत की एक रूपरेखा द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके द्वारा संपत्तियां समर्पित की जाती हैं और शेषों को दैनिक कार्य के उद्देश्य से

मूर्ति को समर्पित परिसर में निवास करने का अधिकार देने वाला प्रावधान है और समय-समय पर की जाने वाली पूजा और त्यौहार मूर्ति के प्रति समर्पण के पूर्ण चरित्र को खराब नहीं करते हैं।

एक विलेख की शर्तों को दूसरे की शर्तों के संदर्भ में समझना, या अलग-अलग शर्तों में बस्तियों के निर्माण पर लागू होने वाले सामान्य नियमों को निर्धारित करना अनुचित है। किसी विलेख का अर्थ निकालने में, न्यायालय को निपटानकर्ता के इरादे का पता लगाना होता है, और उस उद्देश्य के लिए उसकी सभी शर्तों को ध्यान में रखना होता है। यदि, सभी शर्तों की समीक्षा करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी धार्मिक संस्था या देवता के पक्ष में संपत्ति देने के बाद, अधिशेष या तो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से बसने वाले के पास रखा जाता है या उसके उत्तराधिकारियों को दिया जाता है, स्पष्ट रूप से व्यापक शब्द बंदोबस्ती के बावजूद धार्मिक के पक्ष में स्वभाव के अनुमानित आंशिक समर्पण आसानी से किया जा सकता है।

विलेख ईक्स्टी.11ए की शर्तें हालांकि एक स्पष्ट इरादे का खुलासा करती हैं कि पूरी संपत्ति देवता की थी और किसी और का उस पर लाभकारी हित या स्वामित्व नहीं था। शेबैट्स और उनके वंशजों को उक्त संपत्ति में एक निश्चित रुचि दी जाती है, लेकिन यह दिशा देवता को बताए गए पूर्ण हित में कटौती नहीं करती है, न ही इसे सेटलर या उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में लाभकारी हित आरक्षित करने के रूप में समझा जा सकता है। यह निर्देश देवता की संपत्ति पर एक शुल्क बनाने के लिए काम करता है, न कि संपत्ति को एक शुल्क में कम करने के लिए।

इसलिए, पुनर्पूजाकरण करने के लिए, संपत्ति पूरी तरह से देवता के देव-सेवा के लिए समर्पित है। सेटलर या उसके उत्तराधिकारियों के लिए कोई लाभकारी हित आरक्षित

नहीं है: और आय के संचय की दिशा उस समर्पण की वैधता को प्रभावित नहीं करती है। शैबैट्स के रखरखाव और निवास के प्रावधान को इस तरह के समर्पण की एक सामान्य घटना के रूप में देवता की संपत्ति पर प्रतिबंध के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह तय करना अनावश्यक है कि शैबैट्स के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए आय के एक हिस्से के विनियोग के निर्देश वैध हो सकते हैं या नहीं। यदि यह अमान्य है, तो ब्याज देवता को वापस कर दिया जाएगा, न कि बंदोबस्तकर्ता को। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि विलेख ईक्स्टी.11(ए) शैबैट्स और सेटलर के वंशजों के पक्ष में कुछ शुल्क के अधीन एक बंदोबस्ती देवता के लाभ के लिए बनाता है।

1955 के वाद संख्या 67 की कार्यवाही में जो रास्ता अपनाया है, उसे देखते हुए, ईक्स्टी. 11 की शर्तों को निर्धारित करना अनावश्यक है। 1955 का मुकदमा संख्या 67 मूल रूप से बलाई द्वारा दो देवताओं श्री सत्यनारायण जेठ और श्री लक्ष्मीनारायण जेठ और निर्मला के खिलाफ दायर किया गया था, और बलाई ने दोनों देवताओं का प्रतिनिधित्व करने की मांग की थी जो 15 सितंबर, 1944 को बलाई और निर्मला द्वारा निष्पादित किया गया। निर्मला द्वारा कार्रवाई के गठन पर आपत्ति जताने पर सुनील शेखर भट्टाचार्जी को कार्रवाई के लिए दोनों देवताओं का संरक्षक नियुक्त किया गया। भट्टाचार्जी ने बलाई द्वारा किए गए दावे को खारिज करते हुए एक लिखित बयान दायर किया और कहा कि देवता के पक्ष में समर्पण पूर्ण था। बंदोबस्ती की प्रकृति के बारे में एक मुद्दा उठाया गया था और विचारण न्यायालय ने घोषणा की कि बंदोबस्ती आंशिक थी और लाभकारी हित बलाई में निहित था। विचारण न्यायालय ने देवताओं के मामले को खारिज कर दिया था कि पूर्ण समर्पण था, और मुकदमे के संरक्षक ने दोनों देवताओं की ओर से उस डिक्री को चुनौती नहीं दी थी। निर्मला ने अपील की और तर्क दिया कि देवता के पक्ष में पूर्ण समर्पण था, लेकिन वह देवताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी

और वह दावा नहीं कर सकती थी, जब तक कि वह अदालत के आदेश से औपचारिक रूप से खुद को देवता का संरक्षक नियुक्त नहीं कर लेती। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की कुछ संशोधनों के अधीन जो भौतिक नहीं हैं, की पुष्टि की ।

इस अपील में, दोनों देवताओं को भी पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन देवताओं ने इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में भाग नहीं लिया है, जैसा कि उन्होंने उच्च न्यायालय में नहीं किया था। दोनों के खिलाफ फैसला हो गए हैं, देवताओं द्वारा उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं की गई है। जहां तक यह देवताओं के खिलाफ है, डिक्री को चुनौती देना निर्मला के लिए खुला नहीं है, क्योंकि वह देवताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। विचारण न्यायालय के फैसले से विलेख ईएक्स्टी. 11 द्वारा प्रदत्त अधिकार से निर्मला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह इस अपील में अपने लिए विलेख के तहत अधिक ऊंचे अधिकार का दावा करने की मांग नहीं कर रही है, जिसके लिए विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले की शुद्धता की पुनः जांच की आवश्यकता हो सकती है, जहां तक यह देवताओं के शीर्षक से संबंधित है। हालाँकि, यह आग्रह किया गया था कि निर्मला ने अपने लिए जो दावा किया है, उसके अलावा न्यायालय के पास शक्ति है और वह वास्तव में आदेश 41 नियम 33 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत बाध्य है। डिक्री पारित करने के लिए, यदि विलेख के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करने पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विलेख दो देवताओं के पक्ष में पूर्ण समर्पण के रूप में कार्य करता है। आदेश 41 नियम 33 सिविल प्रक्रिया संहिता, जहाँ तक यह भौतिक है, प्रदान करता है:

"अपीलीय न्यायालय के पास किसी भी डिक्री को पारित करने और कोई भी आदेश देने की शक्ति होगी जिसे पारित किया जाना चाहिए और मामले की आवश्यकता

के अनुसार आगे या अन्य डिक्री या आदेश पारित करने या बनाने की शक्ति होगी, और इस शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा किया जा सकता है इस बात के बावजूद कि अपील केवल डिक्री के एक भाग के रूप में है और सभी या किसी भी उत्तरदाताओं या पार्टियों के पक्ष में की जा सकती है, हालांकि ऐसे उत्तरदाताओं या पार्टियों ने कोई अपील या आपत्ति दर्ज नहीं की होगी:"

नियम निस्संदेह ऐसे शब्दों में व्यक्त किया गया है जो व्यापक हैं, लेकिन इसे विवेक के साथ लागू किया जाना चाहिए, और ऐसे मामलों में जहां अपीलकर्ता के पक्ष में हस्तक्षेप के लिए एक डिक्री के साथ भी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है जो स्वीकृति या सहमति से अंतिम हो जाती है ताकि न्यायालय को सक्षम बनाया जा सके। पार्टियों के अधिकारों को समायोजित करने के लिए. जहां अपील में न्यायालय ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचता है जो अपील किए गए न्यायालय की राय से असंगत है और अपीलकर्ता द्वारा दावा किए गए अधिकार को समायोजित करने में उस व्यक्ति को राहत देना आवश्यक है जिसने अपील नहीं की है, आदेश 41 नियम 33 सिविल प्रक्रिया संहिता को उचित रूप से लागू किया जा सकता है। हालाँकि, नियम उन डिक्री को फिर से खोलने का अप्रतिबंधित अधिकार प्रदान नहीं करता है जो केवल इसलिए अंतिम हो गई हैं क्योंकि अपीलीय न्यायालय अपील किए गए न्यायालय की राय से सहमत नहीं है।

1955 के वाद संख्या 67 में निर्मला और देवताओं के खिलाफ किए गए दो दावे, हालांकि एक ही कार्रवाई में शामिल होने में सक्षम थे, अलग थे। देवताओं के विरुद्ध यह दावा किया गया कि संपत्ति आंशिक रूप से उनके पक्ष में समर्पित की गई थी; निर्मला के खिलाफ यह दावा किया गया था कि वह बंदोबस्तकर्ता बलाई के लिए महज एक बेनामीदार थी और निपटान विलेख के तहत वह शेष नहीं थी। उच्च न्यायालय ने यह घोषित करते हुए एक डिक्री पारित की है कि देवताओं के पक्ष में समर्पण आंशिक है



और शैबैत होने के उसके अधिकार की पुष्टि करते हुए आगे कहा है कि निर्मला विलेख द्वारा तय की गई संपत्तियों के संबंध में केवल एक बेनामीदार थी। डिक्री के दोनों हिस्सों के बीच कोई असंगतता नहीं थी, और न तो उच्च न्यायालय में और न ही इस न्यायालय में निर्मला ने अपने लिए किसी ऐसे अधिकार का दावा किया जो विचारण न्यायालय के डिक्री द्वारा उसे दिए गए अधिकार से बड़ा था। विलेख ईएक्स्टी. 11 के तहत निर्मला द्वारा दावा किए गए व्यक्तिगत अधिकारों पर विचार करते समय संयोगवश, यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या देवताओं को पूर्ण ब्याज दिया गया था। इसलिए मुकदमे में प्रतिवादियों के दो समूह थे और मूलतः संबंधित होते हुए भी दो डिक्री पारित की गईं। एक आदेश दूसरे से अलग खड़ा हो सकता है। जब कोई पक्ष डिक्री के खिलाफ अपील न करके प्रथम दृष्टया न्यायालय के डिक्री को अंतिम बनने की अनुमति देता है, तो यह मुकदमेबाजी के किसी अन्य पक्ष के लिए खुला नहीं होगा, जिसके अधिकार अन्यथा डिक्री से प्रभावित नहीं होते हैं, शक्तियों को लागू करने के लिए आदेश 41 नियम 33 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपीलीय न्यायालय अपील न करने वाले पक्ष के पक्ष में डिक्री पारित करना ताकि बाद वाले को वह लाभ दिया जा सके जिसका उसने दावा नहीं किया है। आदेश 41 नियम 33 सिविल प्रक्रिया संहिता का मुख्य उद्देश्य अपीलीय न्यायालय को उस पक्ष को राहत देकर न्याय करने की शक्ति प्रदान करना है जिसने अपील नहीं की है, जबकि ऐसा करने से इनकार करने पर असंगत, विरोधाभासी या अव्यवहारिक आदेश दिए जा सकते हैं। हम यह नहीं सोचते कि आदेश 41 नियम 33 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग इस मामले में देवताओं के पक्ष में किया जा सकता है।

इसलिए 1964 की अपील संख्या 966 और 968 को संपूर्ण लागत के साथ अनुमति दी जानी चाहिए। यह घोषित किया गया है कि विलेख ईएक्स्टी. 11 में

संपत्तियां देवता श्री गोपाल जेठ के पक्ष में पूर्णतः समर्पित थे। इसलिए 1954 का मुकदमा संख्या 79 और 80 खारिज कर दिया जाएगा। हालाँकि, यह निर्मला की ओर से दी गई रियायत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा कि वह विलेख ईएक्स्टी. 11 द्वारा तय की गई संपत्तियों के संबंध में अपने पति बलाई की बेनामीदार थी। 1964 की अपील संख्या 967 बलाई के पक्ष में मय खर्चा खारिज कर दी जाएगी।

बाचावत, जे. विलेख ईएक्स्टी. 11 के संबंध में मेरे विद्वान भाई, शाह, जे. की बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं सहमत हूँ कि विलेख पूरी तरह से देवता के लाभ के लिए एक बंदोबस्ती बनाता है, जो शेबैट्स और सेटलर के वंशजों के पक्ष में कुछ शुल्क के अधीन है।

ईएक्स्टी. 11 में मेरे विद्वान भाई ने माना है कि 1955 के वाद संख्या 67 में पारित डिक्री को चुनौती देना निर्मला बाला के लिए खुला नहीं है। अपने विद्वान भाई के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, मैं इस निष्कर्ष से सहमत होने में असमर्थ हूँ। विचारण न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ईएक्स्टी. 11 के तहत समर्पण आंशिक है और पूर्ण नहीं है, और मुझे लगता है कि निर्मला बाला उच्च न्यायालय में डिक्री को चुनौती देने के लिए खुली थीं, और उच्च न्यायालय में अपील खारिज होने पर, दोनों न्यायालयों की डिक्री को चुनौती देने के लिए वह खुली थीं। इस न्यायालय में एक अपील इस मुकदमे के प्रयोजनों के लिए देवताओं का प्रतिनिधित्व स्वतंत्र अभिभावकों द्वारा पेश की गई थी। लेकिन निर्मला बाला देवता की संयुक्त शेबैट्स में से एक है और उसे डिक्री पर हमला करने का अधिकार है।

महाराजा जगदीन्द्र नाथ राँय बहादुर बनाम रानी हेमन्त कुमारी देवी<sup>(1)</sup> में, सर आर्थर विल्सन ने कहा:

"लेकिन यह मानते हुए कि धार्मिक समर्पण सख्त चरित्र का रहा है, यह बना रहेगा कि समर्पित संपत्ति का कब्जा और प्रबंधन शैबैत का है और यह संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी मुकदमे लाने का अधिकार रखता है। मुकदमे का ऐसा हर अधिकार शैबैट्स में निहित है, मूर्ति में नहीं।"

देवता के संयुक्त शैबैट्स के रूप में, निर्मला बाला को उस डिक्री के खिलाफ यह अपील दायर करने का अधिकार है जो घोषणा करती है कि समर्पण आंशिक है और पूर्ण नहीं है। देवता की संपत्ति की सुरक्षा के लिए ऐसी अपील जरूरी है। अन्य शैबैट्स और देवता अपील के पक्षकार हैं, और मैं यह मानने में असमर्थ हूँ कि अपील निर्मला बाला के कहने पर सुनवाई योग्य नहीं है।

इसके अलावा, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि शैबैट्स अधिकार संपत्ति का अधिकार है। आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ (3) के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी, बीके मुखर्जी, जे. ने कहा:

"कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ [मोनाहाई बनाम भूपेन्द्र] द्वारा यह माना गया था कि शैबैटशिप स्वयं एक संपत्ति है, और इस निर्णय को गणेश बनाम लाल बिहारी में न्यायिक समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और भाबतारिणी बनाम आशालता में भी पहले दो निर्णयों का प्रभाव, जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने पिछले मामले में बताया था शैबैती अधिकार में मालिकाना तत्व पर जोर देना और यह दिखाना था कि कुछ मामलों में यह एक प्रारंभिक तिथि से हिंदू कानून में प्रवेश के रूप में स्वीकार की जाने वाली विसंगति थी। अंगुरबाला बनाम देबब्रत में इस न्यायालय द्वारा इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से अपनाया गया था।"

इस प्रकार यह है कि विलेख ईएक्स. 11(ए) निर्मला बाला का शैबैती अधिकार संपत्ति का अधिकार है यह अधिकार इस घोषणा से प्रभावित है कि विलेख ईएक्स.11(ए) ने एक आंशिक और पूर्ण डेब्यूटर नहीं बनाया। शैबैती अधिकार एक पूर्ण डेब्यूटर है, आंशिक डेब्यूटर में शैबैती अधिकार निश्चित रूप से अलग है। इसलिए अपील के तहत डिक्री निर्मला बाला के शैबैती अधिकार को प्रभावित करती है। वह डिक्री से व्यथित है और इसे अपील में चुनौती देने की हकदार है।

इस मामले को देखते हुए, मेरा मानना है कि 1955 के वाद संख्या 67 में डिक्री के खिलाफ निर्मला बाला की अपील कायम रखने योग्य है। इसलिए, मैंने ईएक्सटी. 11 गुण-दोष के आधार पर अपीलकर्ता के तर्क की जांच की और फिर अपील का निपटारा कर दिया। लेकिन चूंकि बहुमत का मानना है कि अपील सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए पूर्व के संबंध में अपीलकर्ता के मामले की खूबियों की जांच से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

### आदेश

बहुमत के फैसले के बाद, 1964 की अपील संख्या 966 और 968 को मय सम्पूर्ण खर्चा के साथ अनुमति दी जाती है। यह घोषित किया गया है कि विलेख ईएक्सटी.11(ए) में संपत्तियां देवता श्री गोपाल जेठ के पक्ष में पूर्णतः समर्पित थीं। इसलिए 1954 का मुकदमा संख्या 79 और 80 खारिज कर दिया जाएगा। हालाँकि, यह निर्मला की ओर से दी गई रियायत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा कि वह विलेख ईएक्सटी.11(ए) द्वारा तय की गई संपत्तियों के संबंध में अपने पति बलाई की बेनामीदार थीं। अपील क्रमांक 967/1964 बलाई के पक्ष में मय खर्चा खारिज की जाती है।

नोट:- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुभाष चन्द्र कोटिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होना और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।